IMPACT FACTOR 7.50 (SJIAI)

बिहार शोध समागम
BIHAR SHODH SAMAAGAM

Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed /Refereed Open Access Journal
Vol. 4, Issue 4 October-December, 2026
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/
doi.org/10.5281/zenodo.23698360

ISSN : 3048-6971

"बिहार में खादी आंदोलन: गाँधीवादी विचार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण का ऐतिहासिक अध्ययन"

जितेन्द्र कुमार
शोध छात्र, इतिहास विभाग
बी० एन० मंडल विश्व विद्यालय
लालूनगर, मधेपुरा
डॉ० अमरेन्द्र कुमार
शोध निदेशक
स्नातकोत्तर इतिहास विभांग
बी० एन० मंडल विश्वविद्यालय
लालूनगर, मधेपुरा

सार :
खादी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में केवल वस्त्र उत्पादन का माध्यम नहीं थी, बल्कि महात्मा गाँधी के स्वदेशी, स्वावलंबन, श्रम की गरिमा और ग्राम स्वराज संबंधी विचारो की व्यावहारिक अभिव्यक्ति थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खादी के स्वरूप और उद्देश्य में परिवर्तन' आया। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह औपनिवेशिक आर्थिक व्यवस्था के बहिष्कार तथा राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक था, जबकि स्वतंत्र भारत में इसे ग्रामीण रोजगार, कुटीर उद्योग, आर्थिक विकेंद्रीकरण और ग्राम–पुनर्निर्माण के साधन के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया। बिहार में इस परिवर्तन की विशेष ऐतिहासिक महत्ता बढी, क्योंकि चंपारण आंदोलन और गांधीवादी रचनात्मक कार्यक्रमों के कारण यहाँ खादी की मजबूत पृष्ठभूमि पहले से निर्मित थी। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, बिहार विद्यापीठ, बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ तथा जयप्रकाश नारायण जैसे व्यक्तित्वों और संस्थानों ने खादी को ग्रामीण समाज से जोड़ने में योगदान दिया। प्रस्तुत लेख 1950 से 2000 के बीच बिहार में खादी आंदोलन के संस्थागत विकास, ग्रामीण रोजगार, महिला भागीदारी स्थानीय नेतृत्व, उत्पादन एवं बिक्री तथा बदलती बजार व्यवस्था की चुनौतियों का ऐतिहासिक विश्लेषण करता है। उपलब्ध सरकारी आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि बीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक तक खादी एवं ग्रामोद्योग बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बने हुये थे। यद्यपि तकनीकी, पिछड़ापन, वितिय कठिनाईयाँ, विपणन की समस्याएँ और मशीन–निर्मित वस्त्रों की प्रतिस्पर्धा ने इसकी संभावनाओं को सीमित किया फिर भी खादी ने ग्रामीण स्वावलंबन और विकेंद्रीकृत उत्पादन की गांधीवादी अवधारणा को जीवित रखा।

मुख्य शब्दः खादी, गांधीवादी विचार, स्वदेशी, ग्राम स्वराज, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामोद्योग, बिहार, राजेंद्र प्रसाद, जय प्रकाश नारायण, महिला श्रम।

परिचय :–
महात्मा गांधी के आर्थिक चिंतन में खादी का स्थान अत्यंत महत्त्वपूर्ण था। गांधी के लिए खादी केवल कपड़ा तैयार करने की तकनीक नहीं, बल्कि भारतीय समाज के आर्थिक पुनर्गठन का माध्यम था। उनका विश्वास था कि भारत की वास्तविक शक्ति उसके गाँवो में निहित है और ग्रामीण समाज को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाए बिना स्वतंत्रता का उद्देश्य अधुरा रहेगा। चरखा और खादी इसी ग्राम–केंद्रित आर्थिक दृष्टिकोण के प्रतीक बने। इनके माध्यम से गांधी स्वदेशी, स्थानीय उत्पादन, श्रम की प्रतिष्ठा और आर्थिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना चाहते है।।

बिहार में खादी की गांधीवादी पृष्ठभूमि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही विकसित हो चुकी थी। चंपारण सत्याग्रह ने बिहार को गांधीवादी राजनीति और स्चनात्मक कार्यक्रमों से गहराई से जोड़ा। इसके बाद खादी केवल विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का साधन नहीं रही, बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक सुधार और ग्रामीण पुनर्निर्माण की व्यापक प्रक्रिया से जुड़ गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस विरासत को नई परिस्थितियों में आगे बढाने की चुनौती सामने आई। 1950 से 2000 ई० का काल इस दृ ष्टि से महत्वपूर्ण है कि इस अवधि में भारत ने नियोजित आर्थिक विकास, औद्योगीकरण, मशीनीकरण और अंततः आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया को देखा। एक और बड़े उद्योग और मशीन निर्मित वस्त्रों का विस्तार हुआ, दूसरी ओर गांधीवादी चिंतन

छोटे उद्योगों, स्थानीय उत्पादन और ग्रामीण रोजगार की आवश्यकता पर बल देता रहा। बिहार में खादी आंदोलन इसी वैचारिक और आर्थिक द्वंद के बीच विकसित हुआ।

स्वतंत्रता के बाद खादी को संस्थागत आधार देने में डॉ० राजेन्द्र प्रसाद और विहार विद्यापीठ की भूमिका उल्लेखनीय रही। विहार विद्यापीठ गांधीवादी रचनात्मक कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण केंद्र था और स्वतंत्रता के बाद भी चरखा कताई तथा ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में सक्रिय रहा। इससे खादी की पूर्ववर्ती गांधीवादी परंपरा को स्वतंत्र भारत के ग्रामीण विकास से जोड़ने की निरंतरता बनी रही। राज्य स्तर पर भी खादी को विधिक आधार प्रदान किया गया। बिहार खादी एवं ग्रामोद्योग अधिनियम 1956 का उद्देश्य राज्य में खादी एवं ग्रामोद्योग को संगठित, विकसित और विनियमित करना तथा इसके लिए एक बोर्ड की स्थापना करना था। अधिनियम की धारा 14 में बोर्ड के कार्यों के अंतर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग को प्रोत्साहित करना, लोगों को उनके घरों में काम उपलब्ध कराना, आर्थिक सहायता देना, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, प्रशिक्षण केंद्र संचालित करना, कच्चा माल और उपकरण उपलब्ध कराना तथा तैयार उत्पादों की बिक्री और प्रचार की व्यवस्था करना शामिल था। इससे स्पष्ट हैं कि स्वतंत्रता के बाद राज्य की दृष्टि में खादी केवल गांधीवादी आदर्श नहीं रही, बल्कि ग्रामीण रोजगार और उत्पादन की एक संगठित व्यवस्था के रूप में स्वीकार की गई।

बिहार की कृषि प्रधान 'अर्थव्यवस्था में खादी एवं ग्रामोद्योग का महत्त्व इसी संदर्भ में समझा जाना चाहिए। कृषि पर निर्भर ग्रामीण परिवारों के सामने वर्ष भर रोजगार की समस्या रहती थी। खादी और अन्य ग्रामोद्योग कृषि के अतिरिक्त आय और रोजगार का साधन उपलब्ध करा सकते थे। चरखा और करघा जैसे साधनो के माध्यम से कम पूंजी में स्थानीय श्रम का उपयोग संभव था। इस प्रकार खादी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गैर–कृषि रोजगार के एक वैकल्पिक क्षेत्र के रूप में सामने आई।

इस प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। ग्रामीण समाज में महिलाओं का श्रम पहले से ही कृषि, पशुपालन और घरेलू कार्यों में महत्वपूर्ण था, किंतु उसका आर्थिक मूल्य प्रायः औपचारिक रूप से दर्ज नहीं होता था। चरखा और कताई जैसे कार्यों ने महिलाओं की घरेलू जिम्मेदारियों के साथ उत्पादन से जुड़ने का अवसर दिया। गांधीवादी कार्यक्रमों में चरखे को महिलाओं की भागीदारी से जोड़ने का एक कारण यह भी था कि इसे घर पर किया जा सकता था। इस प्रकार खादी ने ग्रामीण महिला श्रम को आर्थिक उत्पादन से जोड़ने का अवसर प्रदान किया। यद्यपि 1950–2000 की पूरी अवधि के लिए बिहार में महिला खादी श्रमिकों की वर्षवार प्रमाणित संख्या उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस संबंध में अनुमानित ऑकडे प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा। फिर भी खादी के सामाजिक इतिहास में महिलाओं के योगदान की उपेक्षा नहीं की जा सकती है।

बिहार के खादी आंदोलन का एक अन्य महत्त्वपूर्ण पक्ष स्थानीय गांधीवादी नेतृत्व था। स्वतंत्रता के बाद जयप्रकाश नारायण का चिंतन धीर–धीरे राजनीतिक संघर्ष से सर्वोदय और ग्राम स्वराज की दिशा में विकसित हुआ। उन्होंने ग्रामीण समाज की समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्यक्ष रचनात्मक कार्य पर बल दिया। सोखोदेवरा इस प्रयोग का महत्त्वपूर्ण केंद्र बना। यहाँ ग्राम–पुनर्निर्माण, सर्वोदय, खादी और छोटे उद्योगों को एक–दूसरे से जोड़ने का प्रयास किया गया। इस प्रकार खादी बिहार में केवल वस्त्र उत्पादन का कार्यक्रम नहीं रही, बल्कि ग्रामीण समाज के व्यापक पुनर्गठन की प्रक्रिया से जुंड़ती गई। सोखोदेवरा का महत्व इसलिए भी था कि यहाँ गाँधीवादी विचार को केवल राजनीतिक विचारधारा के रूप में नहीं, बल्कि ग्रामीण जीवन के पुनर्गठन के कार्यक्रम के रूप में देखने का प्रयास हुआ। खादी, ग्रामोद्योग, स्थानीय श्रम और आत्मनिर्भरता को एक–दूसरे से जोड़ने की कोशिश की गई। इससे बिहार के खादी आंदोलन को स्थानीय प्रकृति स्पष्ट होती है। यह केवल बड़े राष्ट्रीय नेताओं का आंदोलन नहीं था, बल्कि स्थानीय संस्थाओं और कार्यकर्ताओं ने भी इसे ग्रामीण समाज तक पहुँचाने में योगदान दिया।

खादी की आर्थिक उपलब्धियों का मूल्यांकन उसके उत्पादन और विक्री के ऑकड़ों से भी किया जा सकता है। भारत सरकार के संसदीय अभिलेख में 1998–99 के लिए बिहार में खादी का उत्पादन 2.37 करोड़ तथा विक्री 2.42 करोड़ दर्ज है। इसी वर्ष बिहार के खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र का संयुक्त उत्पादन 142.72 करोड़ और विक्री 131.94 करोड़ रूपये की थी। इन ऑकड़ों के स्पष्ट होता है कि 1998–99 ई० तक विहार में खादी एक व्यापक ग्रामोद्योग व्यवस्था का हिस्सा बन चुकी थी। खादी का प्रत्यक्ष उत्पादन मूल्य ग्रामोद्योगों की तुलना में अपेक्षाकृत कम था, लेकिन इसका महत्त्व केवल आर्थिक मूल्य से निर्धारित नहीं किया जा सकता। खादी का वास्तविक महत्त्व ग्रामीण रोजगार, स्थानीय उत्पादन, श्रम–प्रधान अर्थव्यवस्था और गांधीवादी स्वावलंबन की अवधारणा में निहित था।

सदी के अंतिम दशक में खादी को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मशीन से निर्मित वस्त्रों का विस्तार, उपभोक्ताओं की बदलती पसंद, उत्पादन' लागत, तकनीकी सीमाएँ और विपणन की समस्या ने खादी संस्थानों पर दवाव बढ़ाया। इस परिस्थिति में खादी के सामने केवल उत्पादन बढ़ाने की समस्या नहीं थी, बल्कि आधुनिक बाजार के साथ अपने संबंध को पुनर्गठित करने की चुनौती भी थी। बिहार में इन समस्याओं का प्रभाव विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण था, क्योंकि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार और आय की समस्या पहले से गंभीर थी। खादी की श्रम–प्रधान उत्पादन पद्धति एक और रोजगार की संभावना बढ़ाती थी, वहीं दूसरी ओर मशीन–निर्मित वस्त्रों के साथ मूल्य और उत्पादन की प्रतिस्पर्धा कठिन बनाती थीं। इस विरोधाभास ने खादी संस्थाओं के सामने तकनीकी सुधार और गांधीवादी उत्पादन–पद्धति के बीच संतुलन का प्रश्न खड़ा किया।

फिर भी इसे केवल खादी की विफलता कहना उचित नहीं होगा। 1950–2000 ई० के दौरान खादी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वैकल्पिक रोजगार और स्थानीय उत्पादन की संभावना को बनाए रखा। राज्य की नीतियों और संस्थागत प्रयासों ने इसे आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण और विपणन से जोड़ने की कोशिश की। इस प्रकार खादी आंदोलन का मूल्यांकन केवल उसके उत्पादन मूल्य से नहीं, बल्कि उसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव से भी किया जाना चाहिए।

गांधीवादी दृष्टिकोण में ग्राम स्वराज का अर्थ केवल राजनीतिक विकेंद्रीकरण नहीं था। उसका आर्थिक पक्ष भी था – गाँव स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हों। खादी इसी आर्थिक दृष्टि का प्रतीक थी। इसका उद्देश्य बड़े उद्योगों का पूर्ण निषेध नहीं, बल्कि ग्रामीण समाज को ऐसी आर्थिक गतिविधियों से जोड़ना था जिनमें स्थानीय श्रम और संसाधनों का उपयोग हो सके। बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में इस दृष्टिकोण का विशेष महत्व था। यहाँ बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवार कृषि पर निर्भर थे और अतिरिक्त रोजगार की आवश्यकता थी। खादी एवं ग्रामोद्योग इस समस्या का पूर्ण समाधान नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गैर–कृषि रोजगार का एक वैकल्पिक क्षेत्र उपलब्ध कराया। 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण के बाद यह प्रश्न और अधिक महत्वपूर्ण हो गया कि खादी आधुनिक बाजार में अपनी जगह किस प्रकार बनाए रखे। केवल गांधीवादी प्रतीक होने के कारण खादी का बाजार सुशक्षित नहीं रह सकता था। गुणवत्ता, डिजाइन, उत्पादन तकनीक, विपणन और उपभोक्ता को बदलती पसंद के अनुरूप परिवर्तन आवश्यक था। यही वह बिंदु था जहाँ गांधीवादी आत्मनिर्भरता और आधुनिक बाजार के बीच तनाव स्पष्ट दिखाई देता है।

फिर भी खादी की सामाजिक और ऐतिहासिक प्रासंगिकता समाप्त नहीं हुई। ग्रामीण रोजगार, स्थानीय संसाधनों का उपयोग, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, श्रम की प्रतिष्ठा और उत्पादन के विकेंद्रीकरण जैसे प्रश्न आज भी ग्रामीण विकास की बहस के केंद्र में है। इस दृष्टि से 1950–2000 ई० का बिहार का खादी आंदोलन केवल अतीत की आर्थिक गतिविधि नहीं, बाल्कि ग्रामीण विकास की वैकल्पिक अवधारणाओं के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है।

निष्कर्ष

1950 ई0 से 2000 ई० के बीच बिहार में खादी आंदोलन को इतिहास गांधीवादी आर्थिक चिंतन को स्वतंत्र भारत की ग्रामीण परिस्थितियों में लागू करने के प्रयास का इतिहास है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान खादी राष्ट्रीय स्वाधीनता, स्वदेशी और औपनिवेशिक आर्थिक व्यवस्था के विरोध का प्रतीक थी, जबकि स्वतंत्रता के बाद इसे ग्रामीण रोजगार, ग्रामोद्योग आार्थिक विकेंद्रीकरण और आत्मनिर्भरता से जोड़ने का प्रयास किया गया।

डॉ० राजेन्द्र प्रसाद और बिहार विद्यापीठ ने गांधीवादी रचनात्मक कार्यक्रमों की संस्थागत निरंतरता बनाए रखने में योगदान किया। बिहार खादी एवं ग्रामोद्योग अधिनियम, 1956 ने इस क्षेत्र को विधिक आधार प्रदान किया और घरेलू रोजगार प्रशिक्षण, कच्चे माल, औजार तथा विपणन जैसी व्यवस्थाओं को संस्थागत रूप दिया। जयप्रकाश नारायण का सोखोदेवरा प्रयोग खादी के ग्राम स्वराज और सर्वोदय की व्यापक अवधारणा से जोड़ने का महत्त्वपूर्ण उदाहरण था। महिलाओं की भागीदारी ने इस आंदोलन को घरेलू श्रम और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोडने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। 1998–99 ई० के सरकारी आँकड़े बताते हैं कि बिहार में खादी का उत्पादन 2.37 करोड़ और बिक्री 2.42 करोड़ रुपये थी, जबकि खादी एवं ग्रामोद्योग का संयुक्त उत्पादन 142.72 करोड़ रूपये था। इससे स्पष्ट हैं कि सदी के अंत तक खादी और ग्रामोद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था का संगठित हिस्सा बने हुए थे, यद्यपि खादी की अपनी उत्पादन क्षमता पर बाजार और तकनीकी चुनौतियों का प्रभाव पड़ रहा था।

अतः बिहार में खादी आंदोलन को न तो पूर्ण सफलता और न ही विफलता के रूप में देखना उचित होगा। इसकी वास्तविक ऐतिहासिक उपलब्धि यह थी कि इसने ग्रामीण रोजगार, स्थानीय उत्पादन, महिला श्राम, श्रम की गरिमा गौर आर्थिक विकेंद्रीकरण को विकास की बहस का हिस्सा बनाए रखा। बिहार में खादी गांधीवादी विचारों का ऐसा क्षेत्रीय प्रयोग था, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत स्वतंत्र भारत के ग्रामीण पुनर्निर्माण की आवश्यकताओं से जुड़ी। इसी कारण 1950–2000 ई० के बीच बिहार के सामाजिक और आर्थिक इतिहास को समझने में खादी आंदोलन का अध्ययन विशेष महत्व रखता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

प्राथमिक श्रोत

1- Gandhi, M.K., Economics of khadi, Ahmedabad: Navasivan publishing House, 1941.
2- Gandhi,M.K., constructive programme:its meaning and place, Ahmedabad: Navajivan Publishing House, 1941.
3- Government of Bihar, The Bihar khadi and village industries Act, 1956,Patna.
4- Government ofIndia, state KVI Board-wise production and a sales, 1998-99, New Delhi: Lok Sabha Secretariat.
5- Khadi and village industries commission, Annual repoot, 1998-99, Mumbai: KVIC.
6- prime ministers musem & Library, Jayaprakash Narayan papers, New Delhi.

द्वितीयक श्रोत

7- Prasad, Rajendra, Autobiography, New Delhi: National Book Trust, India.
8- parel, Anthony J., ed., Gandhi: Hind swaraj and other writings, Cambridge,Cambridge : university press, 2009.
9- Kumarappa, J.C.. Economy of permanence, vasanasi: Sarva seva sangh prakashan.
10- Pyarelal, Mahatma Gandhi: The last phase, Ahmedabad:Nava jivan publishing House.
11- Scarfe, Allan and Wendy Scarfe, J.P.; His Biography, New Delhi: orient Blackswan.

सरकारी एवं अन्य श्रोत

12-Government of India, Lok Sabha Debates and parliamentary Questions relating to khadi and village Industries,New Dethi Lok Sabha secretariat.
13- Khadi and village Industries commission, Annual reports, Mumbai: KVIC
14- Government of Bihar, Department of Industries, policy Documents relating to khadi and village industries, Patna.